दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 14 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 164

महत्वपूर्ण एवं खास

रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा

» उन्नाव रेप केस

नईदिल्ली (आरएनएस)। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इसके साथ ही 10 लाख के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को बरी कर दिया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी। इस मामले में सेंगर के भाई को भी दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था।

कोरोना के चलते आईपीएल पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आईपीएल पर रोक लगा दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि हमने किसी भी खेल गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जहां लोग बड़ी संख्या में आईपीएल की तरह इकट्ठा होंगे। कोरोनो वायरस के रोकथाम के लिए यह जरूरी है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे बताया कि कोरोना वायरस को रोकना सबकी जिम्मेदारी है, सर्दी-खांसी के लक्षण दिखने पर घर में रहें और दिल्ली में सभी तरह के सम्मेलन और सेमिनार पर रोक लगा दी गई है और सारे इवेंट रद्द किए जाएंगे। आपको बताते जाए कि दिल्ली में स्कूल-कॉलेज से लेकर सिनेमा हॉल तक सब कुछ 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

55 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के अलग-अलग राज्यों की 55 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज भोपाल में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुरुवार को ज्योतिरादित्य भोपाल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर दो बजे के करीब विधानसभा में अपना नामांकन भरेंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल आए तो पार्टी की ओर से उनका शानदार स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया, रात को शिवराज के घर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर डिनर पर पहुंचे।

आइस फैक्ट्री में नाइट्रोजन रिसाव से महिला की मौत, 20 बेहोश

हज़ारीबाग (आरएनएस)। हजारीबाग शहर के बड़ा बाजार मल्लाह टोली स्थित आइस फैक्टरी में गुरुवार रात करीब 9:20 बजे अचानक विस्फोट हुआ, जिससे वहां अफरातफरी मच गयी। 5000 लोगो की इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहरीली अमोनिया गैस करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैल गई जिससे करीब कई लोग चपेट में आ गए। इस दौरान 20 से अधिक लोग बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बेसुधों की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से प्रभावित लोगों को सदर अस्पताल और अरोग्यम अस्पताल ले जाया गया है।

राज्यसभा में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

» शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने उठाए लोकमहत्व के मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में शुक्रवार को इस सत्र के दौरान पहली बार हुए शून्यकाल के दौरान जहां जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठाई गई, वहीं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की अनुशंसा के बजाए कानून के तहत करने की दिशा में काननू बनाने की मांग की गई। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी जोरशोर से उठाए गये।

राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में शुक्रवार को पहली बार

शून्यकाल चला, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए केंद्र सरकार से उन पर अमल करने की मांग की गई। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकने की दिशा में संसद के इसी सत्र में इस संबंध में प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे सख्त प्रावधानों को शामिल किया जाए, जिसमें दो से अधिक संतान होंने पर ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाएं न मिल सके। वहीं यादव ने कहा कि दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने पर विभिन्न चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी जानी चाहिए। यादव ने कहा कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने से पर्यावरण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला

राज्यसभा में द्रमुक सदस्य पी. विल्सन ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद से कानून बनाए जाने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्ता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि आयोग की स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की खातिर संसद को कानून बनाना चाहिए। विल्सन ने कहा कि अभी सरकार की अनुशंसा पर ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इससे आयोग की स्वायत्ता प्रभावित होती है।

एयर इंडिया को खरीदने बोली लगाने की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकारी एविएशन कंपनी एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने इसके लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया है. पहले ये 17 मार्च 2020 थी. आपको बता दें कि सरकार, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस की अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी और संयुक्त उपक्रम एआईएसएटीएस की 50 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी और एयरलाइंस का मैनेमेंट कंट्रोल भी खरीदने वाले के हाथ में ही रहेगा. इसके लिए इच्छुक खरीदार अब 30 अप्रैल 2020 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जमा कर सकते हैं. आपको बता दें कि एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस है. इसके बेड़े में कुल 146 विमान हैं. साल

» सरकार का एक और बड़ा फैसला

1932 में टाटा एयर सर्विसेज के तौर पर एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी. 1947 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था और एक साल बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया हो गया.

सरकार को अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री पूरा हो जाने का अनुमान है. एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने एफडीआई नियमों में बदलाव भी किया है. नए नियमों के तहत अब एनआरआई भी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी एयर इंडिया में खरीद सकते हैं. इससे पहले एयर इंडिया में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति थी।

केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा

» कैबिनेट की बैठक में लिया गया 4 फीसदी महंगाई भत्ता

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद की एनेक्सी में हुई कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

यहां नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपये से 10 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीएध्डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है। इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था।

बच्चों के खिलाफ यौन अपराध कानून हुआ सख्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया है जिससे इस कानून में हाल ही में किए संशोधन लागू किए जा सकेंगे जिसके तहत बच्चों के साथ यौन शोषण के लिए सजा के प्रावधानों को और सख्त कर दिया गया है। नए नियमों में स्कूलों तथा देखभाल केंद्रों में कर्मचारी का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराना, यौन शोषण वाली सामग्री (पोर्नोग्राफी) को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, उचित आयु पर बाल अधिकार शिक्षा देने के प्रावधान शामिल हैं। इन नियमों के तहत राज्य सरकारों को बच्चों के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति बनाने के लिए कहा गया है जिसे बच्चों के संबंध में काम कर रहे सभी संस्थानों, संगठनों या अन्य एजेंसी को लागू करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को आयु के अनुसार शैक्षिक सामग्री और बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है जिनमें बच्चों को निजी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही इसमें टोल फ्री नंबर 1098 के जरिए चाइल्डलाइन हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है।

भारत में वयस्क आबादी से ज्यादा हैं मोबाइल फोन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि वर्तमान में मोबाइल फोन की संख्या देश की वयस्क आबादी से भी ज्यादा हो गई है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 115 करोड़ 14 लाख 37 हजार 99 (करीब 115.14 करोड़) के स्तर पर पहुंच गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की वयस्क आबादी करीब 108.85 करोड़ है। आंकड़ों के मुताबिक, मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यहां कुल 16.85 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संख्या 9.56 करोड़ से ज्यादा है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6.28 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। 9.26 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में 8.70 करोड़, बिहार में 8.43 करोड़ और तमिलनाडु में 8.18 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। मध्यप्रदेश में यह संख्या 7.48 करोड़, गुजरात में 6.74 करोड़, कर्नाटक में 6.73 करोड़, राजस्थान में 6.53 करोड़, पश्चिम बंगाल में 5.52 करोड़, पंजाब में 3.91 करोड़, ओडिशा में 3.30 करोड़, हरियाणा में 2.77 करोड़, उत्तर पूर्व में 1.21 करोड़,

» ट्राई की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश में 1.05 करोड़ और जम्मू-कश्मीर में 1.03 करोड़ से ज्यादा है।

शहरों में दिल्ली शीर्ष पर

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, शहरों के लिहाज से मोबाइल उपभोक्ताओं के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है। यहां कुल 5.29 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। मुंबई में यह संख्या 3.80 करोड़ है। इसके अलावा, कोलकाता में 2.56 करोड़ और असम में 2.36 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं। दूरसंचार विनियामक ने कहा कि इंटरनेट की व्यापक पहुंच और सस्ते डाटा की वजह से मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। कई लोगों के पास एक से ज्यादा मोबाइल हैं। आने वाले समय में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह कहते हुए धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि धर्म निजी आस्था का मामला है और किसी दूसरे धर्म को अपनाना या नहीं अपनाना व्यक्तिगत फैसला है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने पेशे से वकील याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका वापस ले लें क्योंकि अदालत इसे खारिज नहीं करना चाहती। अदालत ने कहा, श्आप इसे वापस क्यों नहीं ले लेते? हम इसे खारिज क्यों करें। इसके बाद याचिकाकर्ता एवं भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और पीठ ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी। याचिका जब सुनवाई के लिए आई तो अदालत ने कहा कि एक धर्म को मानना निजी आस्था का विषय है और किसी दूसरे धर्म को अपनाना या नहीं अपनाना व्यक्तिगत फैसला है।

पीठ ने कहा कि हमें बताइए कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है या किसी को डरा रहा है, तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है।श् अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का धमकी या प्रलोभन के चलते धर्मांतरण का शिकार होने का कोई कारण नहीं बनता। गौरतलब है कि उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि कई व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन और संस्थाएं दबे-कुचले विशेषकर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को श्डराकर, धमकाकर, पैसे का लालच देकर या चमत्कार, काले जादू और अन्य हथकंडे अपनाकर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि कई व्यक्तिध्संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में एससीध्एसटी का धर्मांतरण करा रहे हैं और स्थिति बहुत चिंताजनक है। सामाजिक और आर्थिक रूप से दबे-कुचले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले पिछले 20 वर्षों में काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 79 प्रतिशत हिंदू हैं जबकि 2001 में हिंदुओं की आबादी 86 प्रतिशत थी। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो श्हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे।

विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे गोपाल राय

नई दिल्ली (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोपाल राय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे। विधानसभा में शहर में कोरोनोवायरस की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा होगी। प्रस्ताव का सदन द्वारा पारित हो जाने की संभावना ज्यादा है क्योंकि विधानसभा में आप के पास बहुमत है। आप ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें हासिल की थीं। सूत्रों के अनुसार, आप चाहती है कि 2010 के प्रारूप के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (आप) संचालित किया जाए।

कोरोनावायरस से लड़ने के लिए सार्क देश बनाए मजबूत रणनीति

» पीएम मोदी ने सार्क देशों को दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोनावायरस से निपटने के लिए सार्क देशों का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाए। इससे हम दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी धरती कोरोनावायरस से जूझ रही है। विभिन्न स्तरों पर, सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक आबादी की एक महत्वपूर्ण संख्या का घर दक्षिण एशिया को यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि हमारे लोग स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि सार्क देशों के नेतृत्व ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाए। हमारे नागरिकों को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे हम दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

रेलवे में सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र से सहयोगः रेल मंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के निजीकरण के प्रयास के आरोपों को गलत बताते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार रेलवे का विस्तार करने, सुविधाओं को बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण के लिये निजी क्षेत्र से सहयोग ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब पांच वर्षो में रेलवे में निवेश संसाधन में ढाई गुणा एवं पूंजी व्यय में करीब तीन गुणा वृद्धि की गई है जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले 12 वर्षो में रेलवे में 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब इतनी बड़ी राशि लगानी पड़े तो सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्या होगा और ऐसे में क्या जनता पर कर लगाना उचित होगा।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति में समझदारी यह है कि निजी क्षेत्र का सहयोग लें, सस्ती ब्याज दर पर पैसा लाएं और निवेश करें ताकि रेलवे में सुविधाएं बढ़ें, विस्तार और सुदृढीकरण हो सके। गोयल ने कहा कि 2013-14 में 54 हजार करोड़ रूपये के बजट की तुलना में इस वर्ष बजट को बढ़ाकर 1.61 लाख करोड़ रूपया कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे में बदली सोच के तहत 58 अति महत्वपूर्ण तथा 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया जो क्षमता उन्नयन, माल की गतिविधि, कोयला क्षेत्र आदि से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस पर परोक्ष निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 60-65 साल अगर सकारात्मक तरीके से काम होता, तब रेलवे की ऐसी हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले साढ़े पांच साल में किसी समस्या से मुंह नहीं फेरा बल्कि समस्याओं को सुलझाने का काम किया।

निगरानी में रखे गए कंपनी के 700 कर्मचारी

» फ्रांस और चीन से लौटे कर्मचारी को हुआ कोरोना

नोएडा (आरएनएस)। भारत में एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा फेज-2 में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का है। बताया गया है कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है वह कुछ दिन पहले फ्रांस और चीन से वापस आया था। नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी उसके इस जानलेवा वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या अब 75 हो गई है।

कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद कंपनी में काम कर रहे सभी 700 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। वहीं इस केस के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 11 हो गई है। इनमें 10 भारतीय और 1 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बता दें कि 11 मार्च तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 टेस्ट पॉजिटिव निकले थे। अब तक आगरा में 7, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 1 और लखनऊ में 1 मरीज में कोरोना को पुष्टि हुई है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहां एक और मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब आगरा में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पता चला है कि जिस महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, वह हाल ही में बेंगलुरू से लौटी है। आगरा से 12 संदिग्धों के सैंपल की जांच में ये एक केस पॉजिटिव पाया गया है।